preference to those areas which are far away from coalfields ?

SHRI R. L. CHATURVEDI : I can say we will consider this.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ : They have not considered even these things. How are they running the Government ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सरकार ने कोयले के इंजिन बनाने बन्द कर दिये हैं और अब वह डीजल इंजिनों का प्रयोग करने लगी है। लेकिन डीजल के लिए हमको विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। किसी भी समय कोई आपत्ति आने पर, या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर, डीजल का आयात बन्द हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की डीज़ल और इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव्ज़ में से किसको देश के हित में बेहतर समझती है और किसको प्रोत्साहन देना चाहती है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव्ज़ बहुत कास्ट्ली पड़ते हैं, क्योंकि उसके ट्रैक मेनटेनेंस पर काफी खर्च करना पड़ता है। लेकिन डीज़लाइजेशन में हमको इतनी परेशानी नहीं होती है। सिर्फ डीजल लोकोमोटिव बनाने की प्राबलम रहती है। डीजल लोकोमोटिव को कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमको डीज़लाइजेशन भी करना है। जहां हम इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन और ओवरहैड एक्विपमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं, वहीं इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अगर डीज़ल का इम्पोर्ट बन्द हो गया, तो सरकार क्या करेगी ? यह देश की सुरक्षा का सवाल है। मंत्री महोदय बिल्कुल गलत जबाब दे रहे हैं।

Expenditure Incurred on Advertisment by Firms

+

*1714. SHRI SURAJ BHAN :
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI SHARDA NAND :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred on advertisement by M/s. B. K. Khanna and Company (P) Ltd., New Delhi ; the Indian Engineer and Commercial Corporaption Ltd., New Delhi ; the Sind Knitwears, Ludhiana ; M/s. Khemka and Company, New Delhi ; M/s. Bharat Vanidhya Private Ltd., New Delhi : and M/s. York Hosiery Mills, Ludhiana during the last three years ;

(b) whether Government have received any complaints about these firms ?

(c) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon ; and

(d) the total amount of advertisement given by each firm to the Patriot, Link and other pro-communist papers in the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDY) : (a) to (d). A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Expenditure incurred on advertise- ment by the companies referred to in part (a) of the question is as follows :

	Name of the company	1966-67 Rs.	1967-68 Rs.	1968-69 Rs.
1	2		3	
1.	Bharat Vanidhya Pvt. Ltd., New Delhi.	23,341	10,812	13,585
2.	M/s. Khemka Aviation Pvt. Ltd.	36	4,443	5,452
3.	Indian Engineering and Commercial Corporation Pvt. Ltd., Kanpur.	66,217	88,076	Not available.

1	2	3
4.	B. K. Khanna and Co. (Pvt.) Ltd., New Delhi.	Advertisement expenditure not shown separately in the Balance-sheet.
5.	Sind Knitwears, Ludhiana	Is not a company registered under the Companies Act.
6.	York Hosiery, Ludhiana (now York Hosiery Mills Pvt. Ltd.)	The firm 'York Hosiery' Mills, Ludhiana was incorporated as a Private Ltd. company only on 14-4-1969 and its first Balance-sheet is not yet due.

(b) No, Sir.

(c) The Department of Company Affairs has not received any complaint during the last five years.

(d) The companies are not required to indicate the company-wise break-up of receipts or expenditure in connection with advertisements in the annual returns filed by them in accordance with the provisions of the Companies Act. Hence the information sought is not available.

श्री सूरज भान : क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में यह बात आई है कि इन सब कम्पनियों का कम्युनिस्ट ममालिक के साथ व्यापार होता है और उनके साथ रुपये के पेमेंट के आधार पर ट्रेड होता है और कम्युनिस्ट ममालिक के कमिशन एजेन्ट्स के रूप में इन कम्पनियों द्वारा उस रुपये का इस्तेमाल एडवरटाइजमेंट्स वगैरह के जरिये से कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य कम्युनिस्ट समर्थक संस्थाओं की सहायता और कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रचार के लिए किया जाता है ; यदि हां, तो क्या सरकार यह गारन्टी देगी कि उस रुपये का इस्तेमाल इस नाजायज कामों के लिए न किया जा सके ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY : This Department has no information regarding that. The question may be addressed to the Ministry of Foreign Trade.

श्री सूरज भान : मन्त्री महोदय ने (डी) के उत्तर में कहा है कि कम्पनीज एक्ट के प्राविजन्ज के अनुसार कम्पनियों को इस खर्च का ब्रेक-अप देने की आवश्यकता नहीं है। क्या सरकार अब कम्पनीज एक्ट के तहत ऐसा प्राविजन करेगी कि ये कम्पनियां इस प्रकार का ब्रेक-अप पेश करे, ताकि सब घपला पब्लिक के नोटिस में आ सके ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY : That is a suggestion for consideration. I will examine it.

श्री कंवर लाल गुप्त : ये कम्पनियां, और बहुत सी दूसरी कम्पनियां, रूस और दूसरे कम्युनिस्ट देशों के साथ व्यापार करती हैं। इन कम्पनियों ने कम्युनिस्ट देशों के साथ यह कान्स्पीरेसी कर रखी है कि इनको अन्डरहैंड मीन्ज से जो बहुत सा पैसा मिलता है, वह कम्युनिस्ट एक्टिविटीज में लगाया जाता है। बहुत से कम्युनिस्ट वर्कर एक्चुअली काम नहीं करते हैं, लेकिन वे इन के मुलाजिम दिखाये जाते हैं। इसके अलावा एडवरटाइजमेंट्स के नाम पर कई कम्युनिस्ट समर्थक पत्रों को सहायता दी जाती है और कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य कम्युनिस्ट एसोसियेशन्स को पैसा दिया जाता है। सरकार ने कम्पनी ला में पोलिटिकल डोनेशन्ज को बन्द कर दिया है, लेकिन वह काम आधा ही हुआ है, पूरा नहीं क्योंकि विदेशों के लोग इस तरह पैसे का प्रयोग करके हमारे अन्दरूनी मामलों में दखल देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई स्टडी की है कि विदेशी लोग हमारी कम्पनियों के जरिये से हमारी राजनीति पर कितना प्रभाव डालते हैं ; यदि

नहीं, तो क्या सरकार कोई हाई-पावर्ड कमीशन या कमेटी बिठाकर इस बात की एसेसमेंट करायेगी कि किस तरह से ये कम्पनियां अपने रीसोर्सिज किसी खास पोलिटिकल आइडियालोजी के प्रचार और विस्तार के लिए खर्च करती हैं? यदि उस जांच के आधार पर सरकार को मालूम हो जाये कि यह बात सही है, तो क्या वह कानून के द्वारा इस बात पर पाबन्दी लगायेगी कि कम्पनियां अपना पैसा किसी पोलिटिकल आइडियालोजी के लिए खर्च करें?

SHRI RAGHUNATHA REDDY : I have given the figures of advertisement in the statement. The figures speak for themselves. I do not want to express any opinion about that.

In respect of other matters raised by the hon. Member, there are a number of companies in India which carry on trade and other kinds of economic collaboration with the Communist countries. This Ministry does not have information ; the Ministry of Foreign Trade may be able to give the answer.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया । मैं ने यह कहा कि क्या इस प्रकार का असेसमेंट करेंगे कि यह कम्पनियां इस प्रकार से गोलमाल करती है, कम्युनिस्ट कंट्रीज से मिलकर कम्युनिस्ट ऐक्टिविटीज इसका आप सर्वेक्षण करेंगे और कोई कानूनी पाबन्दी लायेंगे ? दोनों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया । मैं चाहूंगा कि फखरुद्दीन साहब इसका जवाब दें ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, हमारे पास जैसा कि मेरे कुलीग ने कहा कोई इत्तिला ऐसी नहीं है । अगर आनरेबल मेम्बर के पास कोई स्पेसिफिक इत्तिला हो और वह हमें दें और हम समझते हैं कि इससे हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए जरूर हम कार्यवाही करने का ख्याल करेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या मंत्री महोदय इस बात की जानकारी रखते हैं...

श्री कमलनयन बजाज : प्वाइंट आफ आर्डर सर । यह सवाल पूछने से पहले बाहें चढ़ाते हैं, इससे हमें डर लगता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो डरने वाले नहीं है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या मंत्री महोदय इस बात की जानकारी रखते हैं कि बहुत से राजनैतिक दल या तो स्वयं या किन्हीं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अखबार चलाते हैं, रिसाले चलाते हैं, मैगजीन निकालते हैं और विशेष समारोहों और विशेष मौकों पर विशेषांक निकालते हैं और सौवेनियर्स निकालते हैं और इसके लिए भी इश्तिहार इकट्ठे किये जाते हैं...

श्री रवि राय : जैसे बम्बई में निकला था ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हमारे यहां भी निकला, आपके यहां भी निकाला जाता है, सब जगह निकाला जाता है । इन इश्तिहारों की कीमत साधारण इश्तिहारों से ज्यादा होती है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे इश्तिहार भी मंत्रालय की ओपिनियन में प्रतिबन्धित काम का एक अंश समझे जाते हैं ? इस पर पाबन्दी लगी है क्या ? और इसके अंश पर पाबन्दी लगी है क्या ? और दूसरे, अगर ऐसे कामों पर पाबन्दी लगी है तो कम्पनियां के लिए क्यों कि देने वाला पछताता है, ले देने वाला पछताता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय कोई उसके लिए सूचनायें या हिदायतें इस सिलसिले में जारी करने का प्रयास करेगा क्या ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY : The law in this aspect, the hon. Member is aware of, has amended under Sec. 293 A of the Companies Act. In what manner the law has to be interpreted and what should be its effect—I am not here to give a legal opinion on the question.

SHRI N. K. P. SALVE : It is no question of legal opinion. This information...

MR. SPEAKER : Order please. The simple question is : whether in such cases Government is contemplating a ban on that. It is no question of legal opinion.

SHRI RAGHUNATHA REDDY : I may respectfully submit that under Sec. 293 A, as the law as amended stands, the companies are prohibited from making donations to political Parties or for political purposes. The companies can give advertisements to newspapers. Suppose, the advertisement fee given is so disproportionate, probably it may be a matter for the court's interpretation. I cannot say anything on that.

SHRI K. LAKKAPPA : There is one company called Dalmia Sahu Jain which has supplied calendars to all Members of Parliament wherein all the photographs of all political leaders have been published including that of Mr Fakhruddin Ali Ahmed and Mr. A. K. Gopalan. (*Interruptions*) It looks as if the leaders of all the political Parties have taken money from the Dalmia Sahu Jain Group. If such clandestine photographs are published in the calendars supplied by Dalmias, is there any restriction by the Government to ban such clandestine advertisements ? What action is the Government going to take against the Dalmia company regarding this ? Will the Minister explain the position because members are supplied the calendars.

MR. SPEAKER : Mr. Lakkappa, you are asking a very specific question, but I am sorry, this is not within the scope of the question.

SHRI K. LAKKAPPA : Sir, I am asking a very relevant question. These companies are paying money for advertisement and for propaganda of political parties. Why is this company is allowed to print photos of political leaders in advertisements in such a way that it gives the image that political leaders are taking money from the company ? Why should this company be allowed to use such advertisements ? This is my specific question. What is the answer which Government can give ?

MR. SPEAKER : You are a distinguished lawyer yourself. You can ask a question in general terms about advertisement but not in respect of a particular company. He is not in a position to answer.

SHRI K. LAKKAPPA : My question is very specific

SHRI BAL RAJ MADHOK : These are the companies of people who are Russia's men and they support only those who are Russia's men.

MR. SPEAKER : You are taking a chance in between out of nothing.

SHRI K. LAKKAPPA : My question should be answered, Sir. Why should they allow such advertisement ? It is misuse of all political leaders.

MR. SPEAKER : He is not in a position to answer.

SHRI A. SREEDHARAN : He has put a general question on principle, Sir.

SHRI K. LAKKAPPA : Leaders' photos are allowed freely by this company-wallah. I would like to know why such a restriction has not been put in respect of advertisement of political leaders.

MR. SPEAKER : He is not in a position to answer that.

SHRI K. LAKKAPPA : I seek your protection, Sir. You may kindly direct the Minister to answer that question. They should ban such advertisements.

SHRI RAGHUNATHA REDDY : As you were pleased to observe, Sir, Mr. Lakkappa is a very distinguished lawyer. If the law of the land is such and if 293 A can be interpreted to mean prohibition of

advertisements by way of printing of leaders' photos, certainly it will come within the purview of that : otherwise it will not.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मुझे लिखा था कि सोवेनियर्स को जो विज्ञापन और इश्तिहार दिये जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने कम्पनियों को एक सर्कुलर भेजा है तो उसके जवाब में उन्हें क्या उत्तर आया है और क्या वह कोई कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं ?

दूसरी बात यह है कि कम्पनियों के द्वारा इश्तिहारों और विज्ञापनों पर जो खर्च होता है क्या उसके ऊपर कोई कानूनी सीलिंग लगाने की बात वह सोच सकते हैं या उसके ऊपर कोई नया टैक्स लगाने की बात भी सरकार सोच सकती है ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY : As the hon. Member has observed, the Government brought forward some law which the Parliament has passed, and also this was communicated to the companies and business organisations, drawing their attention to the provisions of the law, which prohibit donations to political parties. I am not able immediately to recollect whether any response was there for this circular.

श्री मधु लिमये : सीलिंग के बारे में बतलाइये ।

SHRI F. A. AHMED : After this matter has been considered cerefully by us, I shall keep this suggestion in mind to see if any ceiling is called for.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं राजनीतिक दलों के बारे में सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक विशेष चीज की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । जो बड़ी-बड़ी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज हैं, वे इश्तिहार दिया करती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इश्तिहार देती हैं, जिन पेपरों का उन कम्पनीज के साथ डाइरैक्ट या इनडाइरेक्ट सम्बन्ध होता है और उसके लिये वे मैक्सिमम-मनी उनको देती हैं । वे ऐसा मुनाफे को कम करने के लिए या इन्कमटैक्स की चोरी करने के लिए करती हैं । क्या सरकार कम्पनी कानून में कोई ऐसा संशोधन लायेगी, जिसके अनुसार मुनाफे सीलिंग सेल की सीलिंग और कैपिटल की सीलिंग, मुकर्रिर कर दी जाय, यानी कितने फीसदी से ज्यादा इश्तिहार नहीं दिये जा सकते ? इसके साथ ही क्या आप ऐसी अमेन्डमेन्ट लाने के लिए भी तैयार हैं कि टोटल एडवर्टिजमेंट का 5 फीसदी से ज्यादा किसी एक अखबार को या किसी अखबार के ग्रुप को इश्तिहार की शक्ल में नहीं दिया जाएगा । क्या आप ऐसा संशोधन लाने के लिए तैयार हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?...

MR. SPEAKER : You are only making a suggestion.

श्री प्रेमचंद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मैं सवाल पूछ रहा हूँ । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस चोरी को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं ?

SHRI REGHUNATHA REDDY : All these aspects suggested by the hon. Member will be examined.

श्री प्रेमचंद वर्मा : ये सुझाव नहीं हैं, इन के जवाब देने चाहियें ।

MR SPEAKER : Now, the question hour is over.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 46 के तहत । अगला प्रश्न फौरन-कोलाबोरेशन के बारे में है । नियम 46 में यह सुविधा है कि मंत्री महोदय यदि चाहें तो उस प्रश्न का उत्तर समय के बाद भी दे सकते हैं। अभी-अभी सरकार ने बीयर बनाने वाली विदेशी कम्पनी के साथ फोरन-कोलाबोरेशन किया है । यह सरकार बिस्कुट बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए बीअर बनाने के लिए विदेशी कम्पनियों से

कोलावेरेशन के एग्रीमेंट कर रही है । मैं चाहता हूँ कि नियम 46 के तहत सोंधी जी के सवाल का जवाब दिलवाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप पुराने पार्लियामेन्टेरियन हैं, फिर भी ऐसी बातें करते हैं। आप चाहते हैं तो मैं बाद में उनसे जवाब भिजवा दूंगा । I am not going to allow this.

SHORT NOTICE QUESTION

Launching of Communication Satellite

+

SNQ No. 36. SHRI D. N. PATODIA :
SHRI G. VISWANATHAN :
SHRI J. MOHAMED IMAM :
SHRI S. K. TAPURIAH :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether a communication satellite is likely to be launched in India in 1972 ;

(b) whether Government have plans to use television for educational purposes ; and

(c) if so, the steps which Government have taken in this regard ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The National Aeronautics and Space Administration of U. S. A. is proposing to launch a synchronous satellite in 1973. The Government of India in the Department of Atomic Energy have reached an understanding with NASA for using the facilities available in this satellite for an experiment on satellite-based instructional television for about a year.

Taking into account the proposed satellite television experiment as well as the expected expansion of coverage of All India Radio's television net-work in India the Ministry of Education propose to exploit television as a powerful tool for education. It is also proposed to integrate plans regarding audio-visual education, school radio broadcasts, educational television, teacher training programmes and programmes for upgrading science education.

The following steps have already been taken :—

1. A Special Cell has been established in the Ministry of Educational and Youth Services to look after all aspects of software arrangements for educational television.

2. A detailed scheme has been drawn up for inclusion in the Fourth Plan for establishing a Training Centre at a total cost of Rs. 60 lakhs for production of educational television lessons and for training of teachers.

3. Assistance has been sought from the United Nations Development Programme for experts, equipment and for training facilities for Indian personnel.

SHRI D. N. PATODIA : Adult education is the most serious problem in India, and even today, as many as about 70 per cent of our population are illiterate. Looking at the success of the NASA programme in other countries in the world, I have no doubt that adult education problems can be effectively solved only if it is properly arranged on a TV net work all over the country. To that extent, the arrangement with the NASA is welcome. But the answer of the hon. Minister is very much incomplete.

I would like to know from the hon. Minister how many places in India will be covered by the communication satellite system from 1973 on wards ? According to the answer given, it appears that this would be for only one year on an experimental basis. What arrangement do Government propose to make to extend the period byond one year so that facilities for propaganda education may be available to the people and to illiterate masses in the villages for a longer period ?

DR. V. K. R. V. RAO : I am in entire agreement with the hon. Member about the importance of adult literacy and adult education. We hope that the production of these facilities which will enable us to have a link-up all over the country will help us in having a really massive adult education programme.